दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: PLEXHO/Cir/927 09.03.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया **,**

विषय: सदस्यों के लिए परामर्श – होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण भारत को लौटाए गए निर्यात माल का प्रबंधन (परिपत्र संख्या 09/2026-सीमा शुल्क दिनांक 08 मार्च 2026 के अनुसार)

प्रिय सदस्यों,

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (सीबीआईसी) ने दिनांक 8 मार्च 2026 को परिपत्र संख्या 09/2026-सीमा शुल्क जारी किया है, जिसमें **होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के बाद समुद्री मार्गों में व्यवधान के कारण भारतीय बंदरगाहों पर वापस आने वाले निर्यात माल के लिए एक विशेष प्रक्रिया** निर्धारित की गई है ।

व्यापार को सुगम बनाने और ऐसे माल की सुचारू रूप से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, सीबीआईसी ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143एए के तहत उन निर्यात खेपों को संभालने के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएं प्रदान की हैं जो अपने गंतव्य तक पहुंचने में असमर्थ हैं और भारत लौट रही हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिपत्र में उल्लिखित प्रमुख स्थितियों पर ध्यान दें:

1. **भारतीय क्षेत्रीय जलक्षेत्र के भीतर पोत पर माल लादा गया और ईजीएम/एसडीएम दाखिल नहीं किया गया।**
2. **भारतीय क्षेत्रीय जलक्षेत्र के भीतर पोत पर माल लादा गया हो और ईजीएम/एसडीएम दाखिल किया गया हो, या अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में पोत विदेशी बंदरगाह पर रुके बिना वापस लौट रहा हो।**
3. **भारतीय प्रादेशिक जल सीमा से बाहर स्थित कोई पोत किसी विदेशी बंदरगाह पर रुकने के बाद (कंटेनर उतारे बिना) वापस लौट रहा है।**

सदस्यगण ध्यान दें कि सीमा शुल्क अधिकारी ऐसे शिपमेंट के संबंध में **पहले से वितरित किए गए निर्यात प्रोत्साहनों जैसे आईजीएसटी रिफंड या ड्रॉबैक की वसूली** भी सुनिश्चित करेंगे । उपरोक्त छूट **परिपत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के लिए वैध** है ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संपूर्ण जानकारी के लिए संलग्न परिपत्र को देखें।

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260309125744.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल